कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वर्ष: 64 अंक: 11 मुम्बई अक्टूबर-2020

151 वीं गांधी जयंती पर महात्मा को नमन

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

रखंड .64 अंक .11 मुम्बई अक्टूबर–2020

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

संपादकीय मण्डल

अध्यक्ष
सुश्री प्रीता वर्मा

संपादक
एम.राजन बाबू

सह संपादक
स्मिता जी. नायर

उप संपादक
सुबोध कुमार

अवर उप संपादक
शिव दयाल कुशवाहा

डिजाईन व पृष्ठ सज्जा
शिव दयाल कुशवाहा

वरिष्ठ हिन्दी अनुवाद अधिकारी
सरस्वती खनका

प्रचार, फिल्म व लोक शिक्षण
कार्यक्रम निदेशालय
द्वारा
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,

3,इर्ला रोड,
विले पार्ले पश्चिम, मुंबई-400056
के लिए ई-प्रकाशित
दूरभाष .: 2671 9465, 2671 6323
ई मेल :editorialpublicitykvic@gmail.com
वेबसाइट : www.kvic.org.in

आवश्यक नही कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग व संपादक सहमत हों

इसअंक में.....

समाचार सार ..... ३ - २१

- खादी की ज़ुबानी.....
- केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा गांधीनगर के 20 गाँवों के 200 प्रशिक्षित कुम्हार परिवारों को विद्युत चालित चाक का वितरण .....
- 10 शहरों में 1500 रोजगार सृजित कर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सेवा दिवस मनाया .....
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इनोवेटिव प्रोजेक्ट DigniTea की शुरुआत.....
- केवीआईसी की सख्ती से फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील खादी ब्रांड नाम के उत्पादों को हटाने के लिए मजबूर .....
- मुज़फ्फरपुर में कुम्हारी प्रशिक्षण कार्यक्रम.....
- पूर्वी चंपारण में कुम्हारों के परिवार को दिया गया इलेक्ट्रिक चाक.....
- केवीआईसी के ऑनलाइन बिक्री में पेपर पैकेजिंग के उपयोग की सार्वजनिक सराहना
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री द्वारा हाथ बुनाई कार्पेट क्लस्टर का उदघाटन ..
- रत्नागिरी में पीएमईजीपी जागरूकता शिविर.....
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा वाराणसी में आजीविका टूल्स वितरित .....
- एनएमसी वितरण कार्यक्रम का आयोजन .....
- डिजाइन और फैशन आइकन सुनील सेठी केवीआईसी के सलाहकार नियुक्त.....
- स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए एसपीजी कॉम्प्लेक्स में खादी आउटलेट खुला.....
- दौसा में एनएमसी वितरित .....
- विविध.....
- अमेठी में कुम्हारों को विद्युत चाक का वितरण.....
- केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन.....

प्रेस कवरेज व सोशल मीडिया 22-30

खादी की जुबानी

भारत सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध देश है जिसकी विरासत हजारों साल पुरानी है और मैंने कई शताब्दियों का सफर तय कर इसे आत्मसात किया है। मैंने भारत को ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से आजाद होकर एक मजबूत स्वतंत्र देश के रूप में फलते-फूलते देखा है।

"गांधीवादी वस्त्र" के रूप में, मैं लाखों लोगों की पोशाक बनी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मैंने भारत के लोगों को आत्मनिर्भर होना सिखाया। मैं सिर्फ वस्त्र नहीं, बल्कि एक विचारधारा हूं। मैं अतीत हूं, वर्तमान और भविष्य भी हूं। मैं मूल रूप से भारतीयता की भावना हूं। मैं "ज्ञभ।क्प" हूं।

जब खादी का उल्लेख होता है तो आंखों के सामने जो पहली छवि बनती है, वह है हाथ में सूत लिये "चरखे" पर कताई करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। वे एक ऐसे महामानव थे, जिन्होंने मुझे स्वदेशी आन्दोलन का सबसे महत्त्वपूर्ण हथियार बनाया।

बदलते समय में खुद को प्रासंगिक बनाए रखना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था। देश अब आधुनिक समय में है, और खादी अब नए अवसर के साथ मौजूद है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति से खादी के पुनरोत्थान का आह्वान किया, जिसके परिणाम आश्चर्यजनक रूप से उत्साहवर्धक रहे।

प्रधानमंत्री के इस पूरे प्रकल्प का सूत्रधार बना रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' । उन्होंने खादी अपनाने का अनुरोध किया और देशवासियों ने भी उन्हें निराश नहीं किया। 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' साल दर साल 'खादी' की सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। खादी ने विश्व में

खादी की जुबानी

अपनी अलग पहचान बनाई। खादी की इस सफलता का जिक्र हाल ही में, प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया जब उन्होंने 'वोकल फॉर लोकल' का नारा दिया और घरेलू उत्पादों को अपनाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने का आह्वान किया।

हमारा देश घातक कोरोना महामारी से घिरा है। कोरोना वायरस ने विश्व को तबाह किया, भारत की वित्तीय अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हुई है। रोजगार के साधन कम हो रहे हैं और युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी है। उद्योग-धंधे आर्थिक मंदी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

जैसाकि कि विदित है, विशेष अवसरों पर विशेष कदम उठाये जाने चाहिए। आज की जरूरत है देश के हर व्यक्ति को स्वाबलंबी बनाने की, घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की, गरीबों के लिए ग्राम व कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने की, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की।

खादी में देश में नई क्रांति लाने की शक्ति है। खादी विकल्प है, सभी विदेशी उत्पादों का। खादी माध्यम है, किसानों, महिलाओं एवं युवाओं को रोजगार प्रदान करने का। खादी प्रतिबद्ध है, देश की ऊर्जा को नई दिशा देने को। आइए, हम खादी को अपनाए और एक सशक्त, सुरक्षित और स्वाबलंबी भारत का निर्माण करें।

विनय कुमार सक्सेना
अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग

केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा गांधीनगर के 20 गाँवों के 200 प्रशिक्षित कुम्हार परिवारों को विद्युत चालित चाक का वितरण

माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने विद्युत चालित कुम्हारी चाक का वितरण कर अपने संसदीय क्षेत्र में 200 कुम्हारों को सशक्त बनाया गांधीनगर और अहमदाबाद के 20 गांवों के सीमांत कुम्हार समुदाय के 200 परिवारों ने 20 सितम्बर, 2020 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग(केवीआईसी) की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के साथ जुड़कर स्थायी स्वरोजगार की दिशा में एक कदम बढ़ाया है।

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गांधीनगर के संसदीय क्षेत्र में ग्राम रंधेजा में आयोजित एक समारोह में 200 प्रशिक्षित कारीगरों को 200 विद्युत चालित कुम्हारी चाक और अन्य कुम्हारी उपकरण वितरित किए।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चिन्हित किये गए 20 गांवों में से 15 गाँव गांधीनगर जिले के अंतर्गत आते हैं जबकि शेष 5 गाँव अहमदाबाद जिले के हैं। विद्युत चालित कुम्हारी चाक के वितरण से समुदाय के कम से कम 1200 सदस्यों को अपनी उत्पादकता और उनकी आय में वृद्धि करने में लाभ होगा, जो माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है।

श्री अमित शाह ने केवीआईसी की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं जैसे हनी मिशन, कुम्हार सशक्तिकरण योजना, चमड़ा कारीगरों के सशक्तिकरण और डिग्नेटीए परियोजना की सराहना की। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरित करते हुए, चार कुम्हारों के साथ बातचीत की, जिनमें - सलेशभाई प्रजापति, भारतभाई प्रजापति, अवनीबेन प्रजापति और जिग्नेशभाई प्रजापति शामिल थे, जिन्हें कुम्हारी एवं मिट्टी के बर्तनों बनाने में केवीआईसी द्वारा 10-दिवसीय

प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें विद्युत चालित कुम्हारी चाक और अन्य उपकरण प्रदान किए गए। इन कुम्हारों ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे वे बेहतर आजीविका कमा पाएंगे और "आत्मनिर्भर" बन पाएंगे।

श्री अमित शाह ने कहा कि विद्युत चालित कुम्हारी चाक न केवल कुम्हारों को उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि नए उत्पाद बनाने में भी सक्षम बनाएगा, जिससे दशहरा और दीवाली त्योहारों के दौरान उनकी अच्छी आय होगी। उन्होंने प्रत्येक लाभार्थी से अपने समुदाय के व्यापक लाभार्थ हेतु कम से कम 10 अन्य परिवारों को कुम्हार सशक्तिकरण योजना के साथ जोड़ने का आग्रह किया।"सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार कर कुम्हार (प्रजापति) समुदाय का सशक्तिकरण हमारे माननीय प्रधान मंत्री का सपना रहा है। केवीआईसी की कुम्हार सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य मिट्टी के बर्तनों की कुम्हारी कला को संरक्षित करते हुए उनके लिए स्थायी स्थानीय रोजगार पैदा करके कुम्हारों को "आत्मनिर्भर" बनाना है। यह महत्वपूर्ण है कि युवा कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाने की कुम्हारी कला को अपनाएं और देश भर में इसका विस्तार करें।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कुम्हार कारीगरों के उत्पादों की बिक्री के लिए भारतीय रेलवे के साथ अनुबंध कर उचित विपणन चैनल बनाए हैं। "भारतीय रेलवे ने पहले से ही 400 रेलवे स्टेशनों को नामित किया है जहाँ केवल खाद्य और पेय पदार्थ बेचने के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जा रहा है। मैं, रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे और रेलवे स्टेशनों की पहचान करें ताकि हमारे कुम्हारों को एक बड़ा विपणन मंच प्रदान किया जा सके।" उन्होंने, इसके साथ ही कुम्हारों को रेलवे स्टेशनों पर अपने तैयार उत्पादों को बेचने के लिए सहकारी समितियों के गठन की भी सलाह दी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना, जो दिल्ली में माननीय गृह मंत्री के साथ उपस्थित थे, ने गृह मंत्री को केवीआईसी के

contd on ..... Pg. no. 19

10 शहरों में 1500 रोजगार सृजित कर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सेवा दिवस मनाया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितम्बर, 2020 को "सेवा दिवस" के रूप में मनाने के लिए भारत के 10 शहरों में लगभग 1500 व्यक्तियों को विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं का लाभ प्रदान किया है।

पूर्वोत्तर सीमा पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिमी सीमा पर बीकानेर तक और उत्तर में चंडीगढ़ और नई दिल्ली से लेकर दक्षिण में मदुरई और कोयम्बटूर तक केवीआईसी ने स्थानीय रोजगार सृजन के लिए अपनी कल्याणकारी परियोजनाओं के दायरे में विस्तार करने के लिए १४ कार्यक्रम आयोजित किए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) राज्य मंत्री श्री प्रताप चन्द्र षडंगी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हस्त-निर्मित कालीन बनाने के लिए 500 कारीगरों के स्फूर्ति (SFURTI) क्लस्टर का उद्घाटन किया। श्री षडंगी ने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए केवीआईसी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे भारत के पुनरुत्थान के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि खादी भारत को "आत्मनिर्भर" बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, छह अलग-अलग कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इसमें केंद्रीय जूता प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई) , आगरा के सहयोग से चमड़े के कारीगरों (मोचियों) के लिए वाराणसी में पहला पादुका प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र शामिल है। उन्होंने प्रोजेक्ट

डिग्निटी (DigniTEA) के तहत 6 उन्नतशील साइकल-में फिट चाय/कॉफ़ी बिक्री इकाइयों का वितरण किया जो चाय / कॉफी को स्वच्छता के साथ बेचते हुए चाय-विक्रेताओं को सम्मानजनक आजीविका कमाने में सक्षम बनाएगा।

उन्होंने कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत 300 कुम्हार परिवारों को बिजली चलित चाक और हनी मिशन के तहत 20 किसान परिवारों को 200 मधुमक्खी के बक्से वितरित किए। केवीआईसी अध्यक्ष ने वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक में 6 हाथ से संचालित अगरबत्ती बनाने वाली मशीनों को खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के तहत वितरित किया। साथ ही अगरबत्ती बनाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले बांबुसा तुलदा, बांस के 100 पौधे लगाए। इससे अगरबत्ती बनाने के लिए कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सेवापुरी को नीति आयोग ने विशेष रूप से "प्रेरणादायक जिलों" में से एक के रूप में पहचान की है और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए सेवापुरी में कई परियोजनाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं।

अरुणाचल प्रदेश के प्राकृतिक रूप से मनोरम चुलियु गांव में, श्री सक्सेना ने राज्य के पहले रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। इससे कारीगरों को स्थानीय रोजगार सृजित होंगे और स्थानीय रेशम के उत्पादन में वृद्धि होगी। केवीआईसी ने रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र को विकसित करने के लिए एक जीर्ण-शीर्ण सरकारी स्कूल भवन का नवीनीकरण किया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में पिछले 50 वर्षों में रोज़गार सृजन की ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई थी।

केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय रोजगार सृजन के लिए सतत विकास केवीआईसी का प्रमुख केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता "जॉब टू एवरी हैंड" (हर हाथ में काम) के साथ जोड़ा गया है। "यह माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा और अपील है जिसने खादी को एक नई ऊँचाई पर पहुँचाया है। श्री सक्सेना ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि वह खादी को अपना सबसे बड़ा ब्रांड एंबेसडर बनाने के दिशा में नेतृत्व करते रहेंगे।'

उन्होंने नई दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ में स्थानीय बेरोजगार युवकों को 6 साइकिल-माउंटेड चाय / कॉफी बेचने वाली इकाइयां भी वितरित कीं।

स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए, केवीआईसी के अध्यक्ष ने राजस्थान के बीकानेर जिले और तमिलनाडु में मदुरै जिले के कोविलपट्टी में नया मॉडल चरखा वितरित किया। इसी तरह, खादी कारीगरों को विपणन के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए, केवीआईसी ने भोपाल में बरखेड़ी और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दो खादी बिक्री केंद्रों का उद्घाटन किया।

पूर्ण धारणा के साथ बोला गया "नहीं" सिर्फ दूसरों को खुश करने या समस्या से छुटकारा पाने के लिए बोले गए "हाँ" से बेहतर है.
महात्मा गांधी

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इनोवेटिव प्रोजेक्ट DigniTea की शुरुआत

सेवा दिवस, जो माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को चिह्नित करता है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने इस दिन नई दिल्ली में प्रोजेक्ट डिगनिटिए के तहत ६ नवीनतम साइकिल-माउंटेड टी / कॉफ़ी सेलिंग युनिट का वितरण किया। माननीय संसद सदस्य (राज्यसभा) और भाजपा महासचिव श्री अरुण सिंह और माननीय सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना के उपस्थिति में 6 बेरोजगार स्थानीय युवकों को साइकिल पर चाय / कॉफी की बिक्री करने वाली युनिट वितरित किए। ये इकाइयां चाय-विक्रेताओं को, स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थों की बिक्री करके सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने में सक्षम बनाएंगी।

प्रत्येक साइकिल माउंटेड चाय / कॉफी की बिक्री करनेवाली इकाई की लागत 18,000 रुपये है और इसमें चाय, चीनी, कप और स्नैक्स को ठीक से रखने के लिए गैस स्टोव, गैस सिलेंडर, एक छाता, बर्तन और अलग-अलग कंटेनरों का प्रावधान है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वाराणसी, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे विभिन्न शहरों में भी 17 ऐसी इकाइयां

शेष पृष्ठ सं.....19 पर

केवीआईसी की सख्ती से

फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील

खादी ब्रांड नाम के उत्पादों को हटाने के लिए मजबूर

19 सितम्बर, 2020 : खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और ऐसे ही अन्य ई-कॉमर्स पोर्टल्स को 160 से अधिक "खादी" के ब्रांड नाम से वेब लिंक पर बिक रहे उत्पादों को हटाने के लिए मजबूर कर दिया है। यह केवीआईसी द्वारा 1000 से अधिक फर्मों को "खादी इंडिया" ब्रांड नाम का उपयोग करके अपने उत्पादों को बेचने के लिए कानूनी नोटिस देने का ही परिणाम है जिससे खादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और खादी कारीगरों के कार्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कानूनी नोटिस दिए जाने के बाद, खादी ग्लोबल ने अपनी वेबसाइट www.khadiglobalstore.com का उपयोग करना भी बंद कर दिया है और ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने सोशल मीडिया पेजों को भी हटा दिया है और "खादी" ब्रांड नाम का उपयोग करके ऐसी सभी सामग्री और उत्पाद को हटाने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। । केवीआईसी की कार्रवाई से देश भर में कई स्टोर बंद हो गए हैं जो नकली खादी उत्पादों को बेच रहे थे।

ये ई-कॉमर्स पोर्टल "खादी" ब्रांड नाम का उपयोग करके विभिन्न विक्रेताओं के माध्यम से खादी मास्क, हर्बल्स साबुन, शैंपू, सौंदर्य प्रसाधन, हर्बल मेहंदी, जैकेट, कुर्ता और कई ऐसे उत्पादों की बिक्री कर रहे थे। इसने ऑनलाइन खरीदारों के बीच गलत धारणा बनाई कि ये वस्तुएं "खादी" उत्पाद थे । हटाए गए अधिकांश उत्पादों को एक आयुष ई-ट्रेडर्स द्वारा बेचा जा रहा था। इस फर्म ने केवीआईसी से पुष्टि की है कि उसने विभिन्न उत्पादों के लिए 140 लिंक हटा दिए हैं, जिन्हें "वागड़ के खादी उत्पाद" के रूप में बेचा जा रहा था।

खादी उत्पादों की खरीद के लिए माननीय प्रधान मंत्री की अपील के बाद हाल के वर्षों में खादी की लोकप्रियता कई गुना बढ़ने के साथ खादी ट्रेडमार्क के उल्लंघन में तेजी आई है। इस अवसर का अनुसरण करते हुए, कई ऑनलाइन विक्रेताओं ने खादी के नाम पर कई प्रकार के उत्पादों की बिक्री शुरू की । इसके अलावा सैकड़ों स्टोर विभिन्न शहरों में हैं जो नकली खादी उत्पादों को बेच रहे थे। हाल के महीनों में, विशेष रूप से कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान, इस तरह के धोखाधड़ी ऑनलाइन विक्रेताओं का एक बड़ा प्रसार था । हालांकि, ऑनलाइन ग्राहकों को वास्तविक खादी उत्पादों को खरीदने में सक्षम बनाने के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने www.kviconline.gov.in/khadimask पर ऑनलाइन 300 उत्पादों की एक श्रृंखला की बिक्री के लिए अपना ई-पोर्टल लॉन्च किया है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि केवीआईसी ने उल्लंघनकर्ताओं को खादी के नाम पर उत्पाद बेचने से रोकने का विकल्प दिया है या भारी नुकसान की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। श्री सक्सेना ने कहा, "खादी कारीगरों के

शेष पृष्ठ सं.....20 पर

मुज़फ्फरपुर में कुम्हारी प्रशिक्षण कार्यक्रम

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 11 सितंबर 2020 को, बिहार के मुजफ्फरपुर में 50 कुम्हारों के लिए 10-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम मिट्टी के बर्तनों की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करते हुए स्थानीय और स्थायी स्वरोजगार और ग्रामीण पुनरुत्थान की दिशा में एक कदम है।

इलेक्ट्रिक चाक कुम्हार सशक्तिकरण और मिट्टी के बर्तनों की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने का एक साधन है।

पूर्वी चंपारण में कुम्हारों के परिवार को दिया गया इलेक्ट्रिक चाक

कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत बिहार के पूर्वी चंपारण में 23 सितंबर, 2020 को मोतिहारी में श्री राधमोहन सिंह, संसद सदस्य, पूर्वी चंपारण द्वारा कुम्हार परिवार को 150 विद्युत चालित चाकों का वितरित किए गए। केवीआईसी अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना और संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया।

केवीआईसी के ऑनलाइन बिक्री में पेपर पैकेजिंग के उपयोग की सार्वजनिक सराहना

13 सितम्बर: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ई-कॉमर्स उद्योग में कदम रखे केवल दो माह ही हुए हैं और पहले दिन से ही पैकेजिंग सामग्री के रूप में हस्तनिर्मित पेपर का उपयोग कर रहा है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग " ग्रीन केमेस्ट्री"के सिद्धांत पर चलते हुए यह प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य को सार्थक कर रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, तरल पदार्थों की पैकेजिंग जिसमे परिवहन के दौरान रिसाव को रोकने के लिए सामान्यतः प्लास्टिक रैप का उपयोग किया जाता है के अलावा वस्तुओं के पैकेजिंग में हस्तनिर्मित कागज लिफाफे / पैकेट और हस्तनिर्मित दफ़्ती बक्से का उपयोग कर रहा है। केवीआईसी, फेस मास्क पैकिंग के केलिए बेहतर स्वच्छता के उद्देश्य से अब तक इसकी पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का उपयोग कर रहा था, ने विशेष रूप से केला फाइबर से बने हस्तनिर्मित पेपर लिफाफे भी डिजाइन किए हैं जिसे जल्द ही उपयोग में लाया जाएगा।

विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा वस्तुओं की पैकेजिंग में प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से पैदा हो रहे तथा इसी तरह के अन्य गंभीर पर्यावरणीय खतरों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के मद्देनजर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ऐसी पहल महत्वपूर्ण है । ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया है।

हस्तनिर्मित पेपर पैकेट और कार्टन बॉक्स का उपयोग करके, खादी और ग्रामोद्योग आयोग पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के दोहरे उद्देश्य पूरा करने का कार्य कर रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने कुमारप्पा राष्ट्रीय हाँथकागज संस्थान (KNHPI), जयपुर में निर्मित हस्तनिर्मित पेपर पैकेट का उपयोग कर रहा है, जो हस्तनिर्मित पेपर पैकेजिंग सामग्री के निर्माण में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन कर रहा है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि "खादी वस्त्र दुनिया के सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल पहनने योग्य हैं तथा किसी भी

शेष पृष्ठ सं.....20 पर

सूक्ष्म ,लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री द्वारा हाथ बुनाई कार्पेट क्लस्टर का उदघाटन

माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री प्रताप चन्द्र सारंगी तथा खादी और ग्रमोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 16 सितंबर 2020 को खिजीरपुर प्रयाग (उत्तर प्रदेश) में स्फूर्ति क्लस्टर के तहत हस्त बुनाई कार्पेट क्लस्टर का उद्घाटन किया।

रत्नागिरी में पीएमईजीपी जागरूकता शिविर

18 सितम्बर 2020 को रत्नागिरी जिले के अंबाडावे गाँव में पीएमईजीपी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजय हेड़ाऊ, महाराष्ट्र राज्य कार्यालय के राज्य निदेशक श्री ए. एल.मीना, डीसीसीआई के संस्थापक अध्यक्ष श्री.मिलिंद कांबले उपस्थित थे ।

आयोग के अध्यक्ष द्वारा वाराणसी में आजीविका टूल्स वितरित

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना द्वारा वाराणसी में दिनांक 17 सितंबर 2020 को आजीविका टूल्स वितरित करके प्रधान मंत्री जी का जन्म दिवस मनाया।

इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने सीएफटीआई के सहयोग से पदत्राण प्रशिक्षण और उत्पादन कार्यक्रम तथा अगरबत्ती प्रशिक्षण और उत्पादन कार्यक्रम का वीडियो कोंफ्रेंशिंग के माध्यम से उदघाटन किया।

उन्होंने, चाय विक्रेताओं को 5 बाइ- सायकल, 300 कुम्हार परिवार को विधुत कुम्हारी चाक , मधुमक्खी पालकों को 200 मधुमक्खी बक्से वितरित किए तथा

100 बांस के पौंधो का रोपण किया।

वीडियो कोंफ्रेंशिंग के दौरान अध्यक्ष महोदय ने कारीगरों और लाभग्राहियों को आत्मनिर्भर बनने हेतु मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर में वृद्धि हो सके।

एनएमसी वितरण कार्यक्रम का आयोजन

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीकानेर में 17 सितंबर 2020 को चरखा वितरण कार्यक्रम में चरखों का संवितरण किया।

इस अवसर पर 125 नए मॉडल चरखे वितरित किए गए।

डिजाइन और फैशन आइकन सुनील सेठी केवीआईसी के सलाहकार नियुक्त

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारतीय फैशन उद्योग में अपनी विशेष पहचान रखने वाले श्री सुनील सेठी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। सेठी भारत और विदेशों में खादी के प्रचार के साथ-साथ रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइन संबंधी मामलों में आयोग को सलाह देंगे।

श्री सेठी की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए है। इससे पहले, प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सुश्री रितु बेरी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सलाहकार के रूप में कार्य किया, जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है।

श्री सेठी को वैश्विक व्यापार मामलों में चार दशकों का अनुभव है, जहां उन्होंने कई नवीन और सफल पहलों के माध्यम से भारतीय हस्तशिल्प, डिजाइन और वस्त्र उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ़ इंडिया जिसका प्रतिनिधित्व डिजाइनरों द्वारा किया जाता है के अध्यक्ष के रूप में, सेठी भारतीय फैशन उद्योग को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं।खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना ने इस अवसर पर कहा कि इनकी नियुक्ति "स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैशन उद्योग में खादी के सतत विकास की अवधारणा को ध्यान में रख कर की गई है। KVIC ने पहले ही वैश्विक मंच अपनी पहुँच बना लिया है और यहाँ से हमें अब हर अवसर को भुनाना चाहिए।

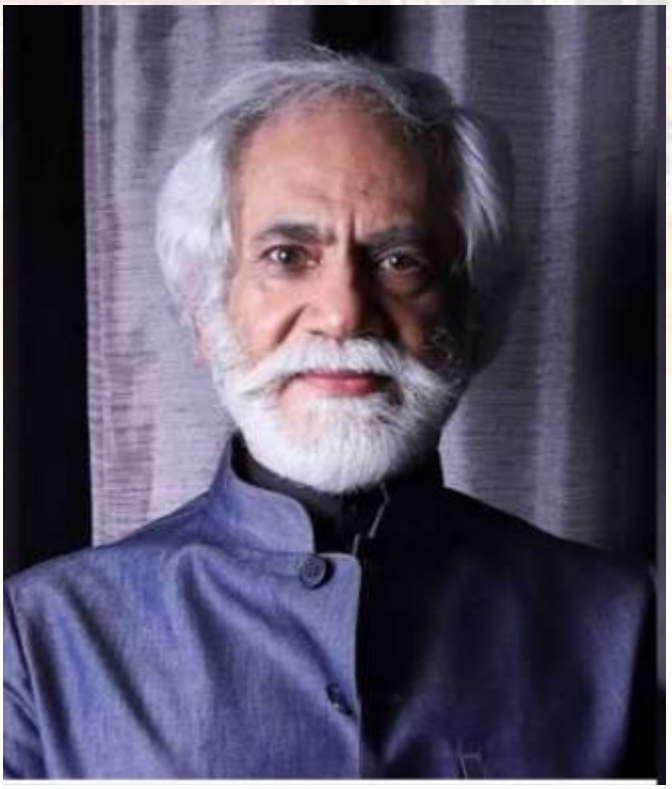

खादी कारीगर दुनिया में बेहतरीन गुणवत्ता और सबसे अनोखे कपड़े का उत्पादन करने में सक्षम हैं और नवीनतम डिजाइन नवाचारों के साथ, खादी एक विशाल वैश्विक उपभोक्ता वर्ग की पसंद बन सकती है।संयोग से, यह भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में माननीय प्रधान मंत्री के "लोकल से ग्लोबल व वोकल फॉर लोकल" आह्वान के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस विकास का भारतीय दस्तकारी उत्पादों तथा इसके प्रति उपभोक्ताओं मे तेजी से फैशन उन्मुख होने के मद्देनजर इसका अधिक महत्व है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सलाहकार नियुक्त किए जाने से पहले, श्री सेठी ने विभिन्न सरकारी निकायों जैसे एचएचईसी, नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम और हस्तकला अकादमी, कपड़ा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में सलाहकार की भूमिकाओं का निर्वहन किया है। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के में सदस्य के रूप में भी कारी किया है।

स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए एसपीजी कॉम्प्लेक्स में खादी आउटलेट खुला

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 26 सितंबर 2020 को दिल्ली में एसपीजी कॉम्प्लेक्स में एक खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। यह आउटलेट एसपीजी के 15,000 से अधिक परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और कई खादी कारीगरों को सशक्त करेगा। यह पहल स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने "स्वदेशी" को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम उठाया है; और इस बार विशेष सुरक्षा दल 'स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप' (SPG) - देश की प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसी के लिए जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में विशेष स्तरीय सुरक्षा के साथ काम करती है; खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने शनिवार को दिल्ली में द्वारका में एसपीजी आवासीय परिसर में एक नए खादी इंडिया बिक्री आउटलेट का उद्घाटन किया। इस आउटलेट से क्षेत्र के दो आस-पास के आवासीय परिसरों में रहने वाले एसपीजी अधिकारियों और कर्मचारियों के लगभग 4000 परिवारों को लाभ मिलेगा। एसपीजी भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक जिम्मेदार एजेंसी है।

खादी बिक्री आउटलेट का उद्घाटन केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना और एसपीजी के निदेशक श्री अरुण सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया।एसपीजी के सदस्यों और उनके परिवारों को शुद्ध और हस्तनिर्मित "स्वदेशी" सामान प्रदान करने के लिए खादी बिक्री आउटलेट खोलने का निर्णय लिया गया था। खादी उत्पादों को खरीदने के लिए इन परिवारों को और प्रोत्साहित करने के लिए, केवीआईसी ने इस आउटलेट में सभी उत्पादों पर 20% छूट देने का फैसला किया है। द्वारका सेक्टर 8 में 125 एकड़ में फैले, एसपीजी कॉम्प्लेक्स, जहां लगभग 15,000 लोग रहते हैं । इसके समीप एक और 26-एकड़ का आवासीय परिसर है, जिसमें एसपीजी कर्मचारियों के 800 से अधिक परिवार हैं और इसलिए, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ खादी आउटलेट स्थित है, में खरीदारों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एसपीजी ने केवीआईसी को 1 रुपये प्रति माह के किराए पर बिक्री केन्द्र प्रदान किया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इस आउटलेट के

माध्यम से केवीआईसी, एसपीजी परिवारों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले हस्तनिर्मित और प्राकृतिक उत्पाद उपलब्ध कराएगा । 'स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप' माननीय प्रधान मंत्री की सुरक्षा का ध्यान रखता है, जो स्वयं खादी के सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर हैं। श्री सक्सेना ने कहा कि इस खादी बिक्री आउटलेट के साथ, केवीआईसी एसपीजी अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली उपभोग्य वस्तुओं को उपलब्ध करना चाहता है । उन्होंने कहा कि खादी बिक्री आउटलेट खादी कारीगरों के लिए भी एक बढ़ावा होगा और केवल स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण उद्योगों को मजबूत करने से हम लोगों के लिए स्थायी आजीविका पैदा कर सकते हैं।माननीय प्रधान मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल के आह्वान से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है। इससे पहले, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

ने अर्धसैनिक बलों को अपने कैंटीन के माध्यम से केवल "स्वदेशी" वस्तुएं बेचने का आदेश दिया था। हाल ही में, केवीआईसी ने सुरक्षा बलों को सुविधाजनक आपूर्ति के लिए आईटीबीपी के साथ पहले एक एमओयू के बाद, अर्धसैनिक बलों को शुद्ध कच्छी घानी सरसों के तेल की आपूर्ति शुरू की है । केवीआईसी इस आउटलेट के माध्यम से सभी खादी के कपड़े और रेडीमेड वस्त्रों के साथ-साथ ग्रामीण उद्योग के उत्पादों को भी बेचेगा।

दौसा में एनएमसी वितरित

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने दौसा के संसद सदस्य (लोकसभा) श्रीमति जसकौर मीणा की उपस्थिति में 7 सितंबर 2020 को राजस्थान के दौसा जिले में स्थित बिलोना काला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए मॉडल चरखे की जांच की।

पृष्ठ सं 06..... से आगे

कार्यक्रमों में निरंतर समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि माननीय गृह मंत्री, गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए की गई हर पहल के लिए सदैव उपलब्ध रहते हैं।

श्री सक्सेना ने बताया कि देश भर में अब तक 18,000 से अधिक इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए गए हैं, जिससे समुदाय के लगभग 80,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत कुम्हारों की औसत आय लगभग 3000 रुपये प्रति माह से बढ़कर लगभग 10,000 रुपये प्रति माह हो गई है।गुजरात के कई क्षेत्र, विशेष रूप से कच्छ और सौराष्ट्र, पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों की कला के लिए प्रसिद्ध हैं। 2018 में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के शुभारंभ के बाद से, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने गुजरात में लगभग 800 कुम्हारों को प्रशिक्षित किया है। मिट्टी के मिश्रण के लिए केवीआईसी ने उन्हें इलेक्ट्रिक चाक के साथ अन्य

उपकरण जैसे ब्लन्जर मशीनें भी वितरित की हैं, जिसने मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की प्रक्रिया से मानव श्रम को खत्म कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में 3-4 गुना वृद्धि हुई है।

पृष्ठ सं 09..... से आगे

वितरित की।

श्री अरुण सिंह ने केवीआईसी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इसकी कल्पना गरीबों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए की गई है । श्रीमती लेखी का महादेव रोड में स्थित कार्यालय से साइकिलों को श्री सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया । श्रीमती लेखी ने यह भी कहा कि केवीआईसी की यह पहल गरीबों को सम्मान के साथ अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाएगी ।

के वी आई सी के अध्यक्ष ने कहा कि साइकिल -माउंटेड टी / कॉफी बिक्री यूनिट स्थायी स्वरोजगार का सृजन करने का एक नवीनतम और लागत प्रभावी मार्ग है और इन इकाइयों के वितरण का उद्देश्य गरीब से गरीब लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। "ये साइकिल इकाइयाँ अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। इसे चाय / कॉफी की बिक्री के दौरान लॉजिस्टिक आवश्यकताओं और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

अगरबत्ती के कच्चे माल रूप में प्रयुक्त होने वाले बंबूसा तुलदा प्रजाति के 100 बांस के पौधों का रोपण किया गया, जिसे असम से लाया गया और दिल्ली के चाणक्यपुरी में सत्य सदन में लगाया गया । इन बांस के पौधों का एक वर्ष की अवधि में ही शानदार विकास हुआ। बांस और अगरबत्ती उद्योग के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए अच्छे संकेत ।

पृष्ठ सं 12..... से आगे

हितों की रक्षा के लिए आवश्यक रूप से विभिन्न फर्मों को कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं। इस ट्रेडमार्क उल्लंघन का सीधा असर हमारे कारीगरों की आजीविका पर पड़ता है जो वास्तविक हस्तशिल्पी उत्पाद बना रहे हैं।"

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने "खादी इंडिया" ट्रेडमार्क अधिकारों के प्रभावी निगरानी के लिए एक मजबूत ऑनलाइन प्रवर्तन योजना बनाई है। जिसके लिए एक समर्पित कानूनी टीम, मानव और तकनीकी उपकरणों के मिश्रण को नियोजित किया है ताकि खादी के नाम पर बेचे जाने वाले अनधिकृत उत्पादों की एक व्यवस्थित और निरंतर निगरानी और सुनिश्चित की जा सके।

केवीआईसी खादी उत्पादों के निर्माण में लगे सभी पंजीकृत खादी संस्थाओं को भी शिक्षित कर रहा है कि केवल केवीआईसी के साथ उनके पंजीकरण ने उन्हें "खादी" ट्रेडमार्क या "खादी इंडिया" लोगो का उपयोग करने के लिए किसी को अधिकृत करने के लिए अधिकृत नहीं किया है जब तक कि इसके लिए कोई फर्म या कंपनी केवीआईसी से उचित लाइसेंस प्राप्त न कर ले।

पिछले महीने केवीआईसी ने खादी के नाम से अनधिकृत रूप से सौंदर्य प्रसाधन और अन्य उत्पाद बेचने के लिए दो फर्मों - खादी एसेंशियल और खादी ग्लोबल को कानूनी नोटिस जारी किया था। केवीआईसी ने फैबइंडिया से 500 करोड़ रुपये का हर्जाना भी मांगा है जो मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

पृष्ठ सं 14..... से आगे

गतिविधि के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए पर्यावरण संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है"। राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी) के हालिया अवलोकन के संबंध में कई मीडिया के प्रश्नों पर प्रतिक्रिया करते हुए, श्री सक्सेना ने कहा कि "खादी उत्पाद प्राकृतिक हैं और पैकेजिंग के लिए हस्तनिर्मित पेपर का उपयोग हमारे ग्राहकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का तरीका है।

हस्तनिर्मित कागज के पैकेट और बक्से सामान्य प्लास्टिक पैकेजिंग पैकेट की तुलना में भारी होते हैं और इस तरह केवीआईसी को हाथ से बने कागज की लागत के साथ अतिरिक्त कूरियर शुल्क वहन करना पड़ता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त लागत के साथ हस्तनिर्मित पेपर पैकेटों का उपयोग करता है ताकि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान न हो। " कागज के पैकेट में सामान की डिलीवरी के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अपने ऑनलाइन ग्राहकों से सराहना मिल रही है। जोधपुर के एक खादी ग्राहक का कहना है कि कागज कार्टन बॉक्स में खादी और ग्रामोद्योग आयोग से प्रेषण प्राप्त होने पर उन्हें प्रसन्नता हुई है । सुमित माथुर ने कहा कि " दो महीने से भी कम समय में मैंने केवीआईसी ई-पोर्टल पर बार-बार आदेश दिए हैं और हर बार मुझे प्लास्टिक के लगभग शून्य उपयोग का पता चला है।"

दिल्ली के बाद KVIC के ऑनलाइन उपभोक्ता डेटाबेस में दूसरे स्थान पर आने वाले कर्नाटक की एक अन्य खादी ग्राहक, अलका भार्गव ने कहा है कि "खादी इंडिया द्वारा कागज के पैकेट का उपयोग करना पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रयास है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। खादी ग्रामोद्योग आयोग प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करता है जो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। ",

केएनएचपीआई, जयपुर में हाथ कागज पर विशेष प्रशिक्षण के द्वितीय बैच के समापन पर प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम।

बाड़मेर में 5 सितंबर,2020 को चरखा मैकेनिजम पर एक माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

एमडीटीसी, केवीआईसी, दहानू ने 17 सितंबर 2020 को मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 17 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के दमोह में क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम के नवीनीकृत खादी ग्रामोद्योग भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उदघाटन किया।

अमेठी में कुम्हारों को विद्युत चाक का वितरण

राज्य कार्यालय, लखनऊ ने 17 सितंबर, 2020 को गांधी आश्रम, ग्राम परसनवा, जिला अमेठी (यूपी) में प्रशिक्षित कुम्हारों को इलेक्ट्रिक कुम्हारी चाक का वितरण किया।

केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों में राजभाषा तथा इसके नीतियोंके संबंध में जागरूकता बढाने के लिए केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई में 14 सितंबर, 2020 से 29 सितंबर, 2020 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री प्रीता वर्मा ने 14 सितंबर 2020 को हिन्दी पखवाड़े का उदघाटन किया। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वाई के बारामतिकर और उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य कार्यकारी अधिकारी के उद्बोधन से की गई। उन्होंने कार्यालय में राजभाषा के उपयोग पर ज़ोर दिया और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। यह कार्यक्रम कोविड-19 महामारी के दौरान आयोजित किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंशिंग रखना जरूरी था। इसलिए ऐसे समय में डिजिटल और ऑनलाईन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

पखवाड़े के दौरान सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, पवारपॉइंट प्रतियोगिता, हिन्दी कविता,और फोटो केपशन इत्यादि प्रतियोगिता आयोजित की गई।

केवीआईसी के राज्य / विभागीय कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया

रा.का.अहमदाबाद

रा.का.शिमला

एमडीटीसी दहानू

रा.का. महाराष्ट्र

रा.का.भोपाल

रा.का.बेंगलुरु

रा.का. देहरादून

रा.का. त्रिपुरा

रा.का. जम्मू और कश्मीर

रा.का. जयपुर

मं.का. विशाखापत्तनम

मं.का. वाराणसी

मं.का. मदुरै

पीएमटीसी, पांपोर में जैम और जेली प्रशिक्षण कार्यक्रम

पीएमटीसी, केवीआईसी, पांपोर ने 17 सितंबर, 2020 को दक्षिण कश्मीर जिले पुलवामा में जैम और जेली पर 15 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री एस.पी. खंडेलवाल राज्य निदेशक केवीआईसी जम्मू और कश्मीर द्वारा किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन पर श्री अनिल कुमार शर्मा प्राचार्य पीएमटीसी पांपोर भी उपस्थित थे।

प्रेस कवरेज

www.newsband.in | contact@newsband.in 2 Wednesday, 2

Big boost to local production; KVIC gets first order for 1200 Quintal Mustard Oil from ITBP

By Chandrashekhar Hendve

The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has received the first order from Indo-Tibetan Border Police (ITBP) for supplying 1200 quintals of kacchi ghani mustard oil worth Rs 1.73 crore. The purchase order comes just weeks after the MoU signed between KVIC and ITBP on July 31, which is aligned with the Hon'ble Prime Minister's call for "Aatmanirbhar Bharat" and "Vocal for Local". The order will be supplied to ITBP within 30 days from the date of order.

Hon'ble Minister for MSME, Shri Nitin Gadkari lauded KVIC's efforts saying this would encourage local production and empower lakhs of people engaged with village industries.

This order will create additional jobs at the Khadi institutions manufacturing high quality kacchi ghani mustard oil. KVIC has instructed Khadi institutions to work in 3 shifts so as to complete the supply within the stipulated period of 30 days. This order will generate lakhs of additional man hours for Khadi artisans and thus encouraging local production.

The development comes in wake of the instructions of Hon'ble Home Minister Shri Amit Shah to the paramilitary forces to encourage local products in a bid to support the "Aatmanirbhar Bharat Abhiyan". Shri Amit Shah has made it mandatory to sell only "Swadeshi" products through the CAPF canteens across India. The ITBP is the nodal agency appointed by MHA for the procurement of provisions on behalf of all paramilitary forces.

KVIC Chairman Shri Vinai Kumar Saxena welcomed the purchase order saying this was a major step towards strengthening our village industries and empowering the local artisans. "Only by encouraging local production and strengthening our village industries, we can overcome financial distress and create sustainable livelihood for our people. At the same time, our jawans at the border will get the best quality mustard oil. We will ensure the supplies are made before time," Saxena said.

The KVIC and ITBP have signed the MoU for a period of one year which will be renewed further. The next products in the pipeline are cotton mats (dari), blankets, bed sheets, pillow covers, pickles, honey, papad and cosmetics, etc. The total value of oil and dari will be approximately Rs 18 crore.

गांधी जयंती तक 1000 उत्पाद मिल सकेंगे खादी के पोर्टल पर

नई दिल्ली। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती दो अक्टूबर तक अपने पोर्टल पर कम से कम एक हजार उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को यहां बताया कि खादी का पोर्टल इसी जुलाई की सात तारीख को बिक्री के साथ शुरू किया गया था जिसने थोड़े समय में ही देशभर से अपनी उपस्थिति दर्ज की है। उन्होंने बताया कि फिलहाल पोर्टल पर 180 खादी उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और चार हजार से ज्यादा लोगों ने खरीदारी की है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन कम से कम और दस उत्पाद पोर्टल पर बिक्री के लिए जोड़े जा रहे हैं और दो अक्टूबर पर पोर्टल पर उपलब्ध उत्पादों की संख्या 1000 को पार कर जाएगी। इनमें खाद्य पदार्थ, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि खादी उत्पादों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना और स्थानीय शिल्पकारों को सशक्तिकरण करना है। पोर्टल से शिल्पकारों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए नया बाजार उपलब्ध होगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर उपलब्ध उत्पादों की कीमत 50 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक है। श्री सक्सेना ने बताया कि पोर्टल पर [illegible] जहां खादी उत्पादों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है।

ये आर्डर 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले हैं। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। खादी आयोग ने 220 रुपए और इससे अधिक राशि की खरीदारी पर मुफ्त आपूर्ति की व्यवस्था की है। ये आर्डर स्पीड पोस्ट से भेजे जाते हैं।

Khadi masks' popularity soars

KVIC receives repeat order for 10.5 lakh face masks from Red Cross Society

By Chandrashekhar Hendve

Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has received a repeat order and the biggest order so far for supply of 10.5 lakh high quality face masks to the Indian Red Cross Society (IRCS). The new purchase order comes less than a month after its previous order for 1.80 lakh face masks out of which KVIC has already supplied 1.60 lakh face masks to the Society.

The new purchase orders worth Rs 3.30 crore have been received recently and the supply will begin this week only. KVIC will complete the supply of the first order in a couple of days. The face masks will be similar to the ones being supplied as per the first order. The fresh order from IRCS is a result of the excellent quality and timely supply of masks by KVIC.

Hon'ble Minister for MSME, Shri Nitin Gadkari lauded the efforts of KVIC in creating sustainable employment in the country through mask-making activities. He said while face masks became the most effective protective gear against the Corona disease; its production created large-scale employment for the artisans.

The development comes as a big push to the local production as it will create nearly 50,000 additional man days for Khadi artisans. The execution of this order will require over 1 lakh meters of handmade cotton Khadi fabric which will be supplied

Contd. on pg. 6

प्रेस कवरेज

ANALYSIS

THE IMPORTANCE OF AGARBATTI AND DRAGON'S NEFARIOUS DESIGNS

An estimated 5 lakh people, mostly women, are associated with the agarbatti industry in India and lakhs of people are engaged with bamboo cultivation in the country. Malicious campaigns, mostly run by China, against the burning of agarbatti will only end up killing the livelihood of these people

Khadi ramping up digital presence, to add 1,000 new products by Oct 2

OUR BUREAU
New Delhi, September 9

Khadi and Village Industries Commission (KVIC) on Wednesday said it is ramping up online inventory and aims to add at least 1,000 new products by October 2.

KVIC began selling products online from July 7 with Khadi face masks and has gradually added 180 products so far.

"KVIC is adding at least 10 new products to its online inventory on a daily basis and it has set a target of adding at least 1,000 products by October 2 this year. In less than two months, KVIC has served nearly 4,000 customers," an official statement said.

The product range, which is priced from ₹50-5,000, includes hand-spun and hand-woven fine fabric such as muslin, silk, denim and cotton, Khadi's signature wrist watch, honey, herbal and green teas, herbal medicines and soaps, papad, *kacchi ghani* mustard oil and a range of herbal cosmetics among others.

Vinai Kumar Saxena, Chairman, KVIC said,"Earlier, Khadi products were sold only through outlets and hence their visibility was confined to a few States.

However, with KVIC's e-portal, products are now reaching far-flung areas of the country, giving wider marketing spectrum to Khadi institutions which will ultimately increase their production and add to the income of artisans."

He said online sale of Khadi products is a big push to Swadeshi products and KVIC aims at empowering the local artisans.

KVIC said it has received online orders from 31 States and Union Territories that include the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Kerala, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir.

It has fixed the minimum order value at ₹599 for free delivery of goods and has tied up with the Postal Department for delivery of consignments via Speed Post. The online portal was developed in-house by KVIC.

TO ADVERTISE
PLEASE CONTACT
Mumbai : 022 - 22021099
Pune : 020 - 26113743
Ahmedabad : 079 - 26871105
BusinessLine

KVIC to train 500 persons before Gandhi Jayanti

Srinagar Sept 24 : Khadi and Village Industries Commission, Ministry of MSME, Government of India has started campaign to provide trainings to 500 persons on various traditional trades of Kashmir before Gandhi Jayanti. In this connection Training Centre namely Production Cum Marketing Cum Training Centre (PMTC) of KVIC has already started 12 training courses on various trades. It is worth to mention here that PMTC KVIC Pampore has started these training which include computer training at Chrodara Budgam, Tilla embroidery at Kanthpora Baramulla, cutting & tailoring at Karipora Baramulla. PMTC, KVIC on 17.09.2020 started 1 days training course on Jam and Jelly at Samboora area of south Kashmir district Pulwama. PMTC KVIC Pampore on 21.09.2020 started two training programmes at far flung villages of North Kashmir District Bandipora. First training program on computer course was started at Aloosa Bandipora and second training on shawl embroidery was started at Ashtingoo Bandipora.PMTC KVIC Pampore on 22.09.2020 started four training programmes at far flung villages of centre Kashmir District Budgam. First training program on shawl embroidery course was started at Checkshera Khansahib Budgam; second training on Kani Shawl weaving was started at Checkshera Budgam. The third training course on willow works and fourth training on carpet weaving was started at Checkshera Khansahib Budgam.PMTC KVIC Pampore on 24.09.2020 started one month training programme on Tilla Embroidery at Dusu area of South Kashmir District Pulwama. The training programme was inaugurated by Shri Anil Kumar Sharma Principal PMTC Pampore through video conferencing.The training programmes were inaugurated by Shri S.P Khandelwal State Director KVIC, J&K via video conferencing and Shri Anil Kumar Sharma Principal Assistant Director, PMTC, KVIC Pampore was also present on the occasion. Shri S.N Shukla ji, Dy. CEO (NZ) addressed the trainees via video conferencing.On the occasion while giving details about the campaign Shri Anil Kumar Sharma Principal Assistant Director, PMTC, KVIC Pampore stated that as per the instructions of State Director KVIC J&K and other Higher Officers of KVIC, this office have started mission to train 500 persons of Kashmir Region in those traditional trades which are dying and needs revival. He said that State Director desired to revive these traditional trades so that the candidates may be benefited and they can earn their livelihood at their homes. State Director, KVIC, J&K Shri S. P. Khandelwal who addressed the trainees via video conferencing from Jammu stated that He has recently joined as State Director J&K and intends to reach out to the desirable people of J&K U.T. He stated that KVIC has many schemes through which we can provide benefits to the people. Khandelwal said that KVIC is the national Nodal Agency for Prime Minister's Employment Generation programme (PMEGP) under which financial assistance with 35% subsidy is provided and after imparting trainings KVIC will provide handhold support to the trainees under PMEGP. They assured that mission of KVIC will continue in the future also.

mint

In less than two months' time, KVIC has served nearly 4000 customers.

Vocal for local: Khadi's e-market portal gains good traction

2 min read . Updated: 09 Sep 2020, 02:28 PM IST

Staff Writer

The online sale that was launched with just Khadi Face Masks on July 7 this year has evolved into a full-fledged E-market platform with 180 products as on today and many more in the pipeline.

प्रेस कवरेज

42 लाख MSME को 1.63 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हुआ मंजूर

■ एजेंसी, नई दिल्ली। बैंकों ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (MSME) के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ECLGS) के तहत अब तक 42 लाख इकाइयों को 1.63 लाख करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। इस योजना के तहत 10 सितंबर तक 25 लाख MSME को 1.18 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया जा चुका है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से MSME इकाइयां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

यह योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मई में घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा है। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि 10 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा शीर्ष 23 निजी क्षेत्र के बैंकों ने इस योजना के तहत 42,01,576 इकाइयों को 1,63,226.49 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज मंजूर किया है। इसमें से 25,01,999 इकाइयों को 1,18,138.64 करोड़ रुपये का कर्ज दिया जा चुका है।

वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं का ब्योरा साझा करते हुए बयान में कहा गया है कि बैंकों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) तथा सूक्ष्म वित्त कंपनियों (एमएफआई) के लिए 45,00[illegible] करोड़ रुपये की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 के तहत 25,055.5 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो की खरीद को मंजूरी दी है। बयान में कहा गया है कि किसान ने एक अप्रैल, 2020 से आठ सितंबर, 2020 के दौरान 27.55 लाख कार्डधारकों को 1,01,308 करोड़ रुपये का कर्ज जारी किया है।

कोरोना काल में हाथ कागज बनाने का सुअवसर–सक्सेना

जयपुर। कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान सांगानेर में प्रवासी श्रमिक, उद्यमी, नौकरी करने वाले, विद्यार्थियों को कोरोना काल में नया व्यवसाय करने के इच्छुक अभ्यर्थी जो ऐसे क्षेत्र में नवाचार कार्य करते हुए प्रकृति को संतुष्टि देते हुए ऐसे गैर सरकारी संस्थान के लोगों में हाथ कागज और उसके उत्पाद बनाने का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में समापन पर मुख्य अतिथि विनय कुमार सक्सेना अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित करते हुए कहा कि कुमारपा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान में जो भी अभ्यर्थी प्रशिक्षण कर रहे है या करेंगे उनको आयोग की हाथ कागज से सम्बंधित परियोजना से जोड़ा जायेगा एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से उनको उद्योग स्थापित करने के हर संभव मदद किया जायेगा। उन्होंने संस्थान को इस तरह के प्रशिक्षण का आयोजन करने पर प्रशंसा की। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक बद्री लाल मीना ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए एवं उन्होंने भी सभी प्रशिक्षणार्थियों को हर संभव मदद खादी और ग्रामोद्योग की गतिविधियों के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का आश्वासन दिया। मीना ने बताया कि राजस्थान से करीब 100 करोड़ मूल्य के हाथ कागज का निर्यात हो रहा है। नये प्रशिक्षणार्थी उद्यम स्थापित करेंगे और निर्यात करेंगे तो इससे राज्य में अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। इस अवसर पर संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार, ईशा खान, डॉ. साक्षी एवं डॉ. सुनीता चौहान भी उपस्थित थे।

खादी लवर्स के लिए खुशखबरी, खादी पोर्टल पर अब मिलेंगे

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती दो अक्टूबर तक अपने पोर्टल पर कम से कम एक हजार उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि खादी का पोर्टल सात जुलाई को फेस मास्क की बिक्री के साथ शुरू किया गया था जिसने थोड़े समय में ही ई-बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज की है।

प्रतिदिन कम से कम और दस उत्पाद पोर्टल पर बिक्री के लिए जोड़े जा रहे हैं और दो अक्टूबर तक पोर्टल पर उपलब्ध उत्पादों की संख्या 1000 को पार कर जाएगी। इनमें वस्त्र, खाद्य पदार्थ, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन शामिल हैं। फिलहाल पोर्टल पर 180 खादी उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और चार हजार से ज्यादा लोगों ने खरीदारी की है।

आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को यहां बताया कि खादी उत्पादों का उद्देश्य स्वदेशी को बढ़ावा देना और स्थानीय शिल्पकारों का सशक्तिकरण करना है। पोर्टल से शिल्पकारों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए नया बाजार उपलब्ध होगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर उपलब्ध उत्पादों की कीमत 50 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक है।

श्री सक्सेना ने बताया कि पोर्टल पर उन क्षेत्रों से भी लोग खरीद कर रहे हैं जहां खादी उत्पादों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। ये आर्डर 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले हैं। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। खादी आयोग ने 599 रुपए और इससे अधिक राशि की खरीदारी पर मुफ्त आपूर्ति की व्यवस्था की है। ये आर्डर स्पीड पोस्ट से भेजे जाते हैं।

the pioneer

HOME DELHI INDIA BUSINESS WORLD SPORTS OPINION ANALYSIS STATE EDITIONS E-PAPER

Khadi's e-market portal gains traction

Wednesday, 09 September 2020 | PNS | New Delhi

Khadi and Village Industry Commission's (KVIC) venture into the online marketing segment has quickly established a pan-India reach enabling the artisans sell their products to the remotest parts of India through the KVIC E-Portal - www.kviconline.gov.in/khadimask/.

The online sale that was launched with just Khadi face masks on July 7 this year has evolved into a full-fledged E-market platform with 180 products as on today and many more in the pipeline.

The product range includes hand-spun and hand-woven fine fabric like Muslin, Silk, Denim and Cotton, Unisex Vichar Vastra by Ritu Beri, Khadi's Signature Wrist Watch, a variety of honey, Herbal and Green Tea, Herbal Medicines and Soaps, Papad, Kacchi-Ghani Mustard Oil and a range of herbal cosmetics among many others. KVIC is adding at least 10 new products to its online inventory on a daily basis and it has set a target of adding at least 1,000 products by October 2 this year. In less than two months' time, KVIC has served nearly 4000 customers.

KVIC Chairman, VK Saxena said the online sale of Khadi products is a big push to "Swadeshi" and aims at empowering the local artisans. "Khadi's E-market portal is providing our artisans an additional platform to sell their goods. This is a concrete step towards building of Aatmanirbhar Bharat," Saxena said, adding the product range is priced from Rs 50 to Rs 5000, keeping in view the choice and affordability of all sections of buyers," he said.

KVIC has fixed the minimum order value at Rs599 for free delivery of goods. It has entered into an agreement with the Postal Department for delivery of consignments via Speed Post.

नई उम्मीद | आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सैकड़ों कामगारों को मिलेगा लाभ, की जा रही कवायद

पारंपरिक कारीगरी को तकनीक से जोड़ बढ़ाया जाएगा स्वरोजगार

प्रेस कवरेज

खादी के उत्पादों और कारीगरों को बढ़ावा दे रहा है खादी ग्रामोद्योग

कोरोना जैसे वैश्विक संकट के दौर में भी भारत के खादी सेक्टर ने प्रगति की अपनी रफ्तार बनाए रखी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग(केवीआईसी) के प्रयासों से मास्क उत्पादन के रूप में खादी कारीगरों को सशक्तिकरण का नया माध्यम मिला है।

देशभर में 9 लाख मास्क बांटने के बाद अब केवीआईसी अपने ऑनलाइन आउटलेट के जरिए भी मास्क बेच रहा है। आउटलेट और ऑनलाइन बिक्री के जरिए केवीआईसी अभी तक 11 लाख मास्क बेच चुका है। बता दें कि केवीआईसी द्वारा महिला कारीगरों को 3 रुपए प्रति मास्क का भुगतान किया जा रहा है। इस हिसाब से अभी तक 50 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग को हाल ही में इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी से 1 लाख 61 हजार मास्क का ऑर्डर मिला है। इससे 20 हजार मीटर खादी के साथ 9000 श्रमदिवस का उत्पादन होगा।

केवीआईसी अब तक 10 लाख से अधिक फेस मास्क बेच चुका है, जिसमें डबल लेयर्ड कॉटन मास्क और ट्रिपल लेयर्ड सिल्क मास्क शामिल है। अकेले जम्मू-कश्मीर सरकार से अब तक 7 लाख मास्क का ऑर्डर मिल चुका है। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी से प्राप्त ऑर्डर के बारे में केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि खादी के मास्क को बड़े पैमाने पर मांग से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के बड़े पैमाने पर ऑर्डर से हमारे कारीगरों को कठिन समय में आय बढ़ाने का मौका मिलेगा।

KVIC organises Bankers Meeting on PMEGP

STATE TIMES NEWS

SRINAGAR: To review implementation of Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) in Kashmir Division, Khadi & Village Industries Commission (KVIC) on Thursday organised Bankers Meeting on PMEGP through video conferencing.

The meeting was chaired by S.N. Shukla, Dy. Chief Executive Officer (North Zone), KVIC, Ministry of MSME, Govt. of India, State Director KVIC J&K S.P. Khandelwal, Anil Kumar Sharma, Nodal Officer, PMEGP KVIC J&K KVIC, representative of Convenor UTBC, Director Industries & Commerce, Jammu and Lead District Managers, Director RSETIs, KVIC, KVIB and DIC, J&K Grameen Bank, Ellaquai Dehati Bank, SBI, PNB of Jammu and Kashmir Region.

Assistant Director Anil Kumar Sharma briefed about the district-wise and bank-wise progress of PMEGP for the year 2020-21.

Dy. CEO (North Zone), KVIC, S.N. Shukla chairing a meeting through webinar

Addressing the meeting, S.N. Shukla held a detailed review of the PMEGP being implemented by all sponsoring agencies viz KVIC, KVIB & DIC.

He asked the banks to work in right earnest to meet the targets of the programme and expedite disbursement of the margin money.

Shukla further emphasised upon the District Officers to complete their targets within the month and asked them to achieve the new assigned targets, so that more and more unemployed youths are benefitted under this scheme.

Dy. CEO expressed that the discussions held during the review meeting with all the stakeholders, including representatives of various Banks, States officials and other beneficiaries, will be fruitful on crucial areas like collateral free loans, timely bank sanctions, release of margin money subsidy and loan instalment, coverage of credit guarantee scheme, achievement of social category targets of SC, ST, minority, women etc.

The meeting will encourage all the stakeholders and will lead to better implementation of PMEGP Scheme in Jammu and Kashmir Region, thereby achieving the set targets in time and providing better employment opportunities to the youths. The position was reviewed in the meeting and also the bottlenecks were examined. In the meantime, State Director, KVIC J&K emphasised upon the banks to look into the cases which been rejected by various banks and expedite process of claiming of Margin Money (Subsidy) on them in exception of EDP upto 10 September 2020.

State Director was instructed by the Dy. CEO (NZ) to hold the meetings with Director Industries and Commerce of Jammu and Kashmir Region, besides with the Secretary KVIB, J&K for expedition of PMEGP cases so that the tar-

मधमाशी प्रशिक्षण वर्ग प्रथमच ऑनलाइन पद्धतीने

लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : करोना विषाणू संसर्गामुळे शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ऑनलाइन पद्धतीने सुरू आहे. ... मधमाशी पालन प्रशिक्षण वर्ग ऑनलाइन पद्धतीने ...

जाहीर सूचना

VVSS NIDHI LIMITED

NOTICE OF THE 2nd ANNUAL GENERAL MEETING

लोकसत्ता Mon, 07 September 2020 https://epaper.loksatta.com/c/54778122

पत्रिका राजस्थान

कोरोना... पधारो ना म्हारे देस

पोलमपोल 'बॉलीवुड' का थाल में, भाँत-भाँत को ... छोटा-छोटी नकल कर, घणा हुया कढ़ाल

कोरोना की हार तय... क्योंकि हमेशा जलते रहेंगे उम्मीद के दीपक

पत्रिका फोटो स्टोरी

प्रेस कवरेज

के.वी.आई.सी.ने आयोजित की बैंकर मीट, पी.एम.ई.जी.पी.में मिलेंगे रोजगार के अवसर

PMTC KVIC Pampore starts four training programmes

■ STATE TIMES NEWS

BUDGAM: Production-cum-Marketing-cum-Training Centre (PMTC), Khadi & Village Industries Commission (KVIC) Pampore on Tuesday started four training programmes in Central Kashmir Budgam. First training programme on shawl embroidery course was started at Checkshera Khansahib Budgam, second training on Kani Shawl weaving was started at Checkshera Budgam. The third training course on willow works and fourth training on carpet weaving was started at Checkshera Khansahib Budgam. The training programmes were inaugurated by Anil Kumar Sharma, Principal PMTC Pampore. Besides, staff of PMTC were also present on the occasions.

PMTC KVIC Pampore officials interacting with trainee.

Scoop News

The Most Authentic & Accurate Online News Source on Jammu, Kashmir & Ladakh

Top Stories | Jammu News | Kashmir News | Ladakh News | Special Stories | Articles | Letters

News Details

KVIC Organises Bankers Meeting on PMEGP

Friday 11 September 2020 22 Muharram-ul-Haraam,1442 AH

KVIC Organises Bankers Meeting on PMEGP

Srinagar, 10th September 2020 To review implementation of Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) in Kashmir Division, Khadi & Village Industries Commission (KVIC) organised Bankers Meeting on PMEGP on Thursday through Video Conferencing.

The Meeting was chaired by S.N. Shukla, Dy. Chief Executive Officer (North Zone), KVIC, Ministry of MSME, Govt. of India, S. P. Khandelwal, State Director State Office J&K, Shri Anil Kumar Sharma, Nodal Officer, PMEGP, KVIC J&K KVIC, Representative of Convenor UTBC, Representatives of Director Industries & Commerce, Jammu and Lead District Managers, Director RSETI's, Representatives of KVIC, KVIB and DIC, Representative of J&K Grameen Bank, Ellaquai Dehati Bank, SBI, PNB of Jammu and Kashmir Region were present during the Meeting.

In the beginning of the meeting Assistant Director Shri Anil Kumar Sharma briefed the meeting and all present during the meeting about the District-Wise and Bank-Wise progress of PMEGP for the year 2020-21. Anil Kumar gave powerpoint presentation for FOR 2ND FINANCIAL ASSISTANCE UNDER PMEGP FOR EXPANSION OF THE EXISTING SUCCESSFUL PMEGP Units.

Addressing the meeting S.N. Shukla held a detailed review of the PMEGP being implemented by all sponsoring agencies viz KVIC, KVIB & DIC.

He said PMEGP is the flagship scheme of Ministry of MSME and is an effective instrument for generating employment opportunities in urban and rural India through setting up of micro enterprises. He said PMEGP is an effective scheme to tackle unemployment, generate sustainable employment opportunities in rural and urban areas and financial institutions like banks play a crucial role here. "He asked the banks to work in right earnest to meet the targets of the programme and expedite disbursement of the margin money.

Shukla, further emphasised upon the District Officers to complete their targets within the month and asked them to achieve the new assigned targets, so that more and more unemployed youths are benefited under this scheme.

Dy. CEO expressed that the discussions held during the review meeting with all the stakeholders, including representatives of various Banks, States officials and other beneficiaries, will be fruitful on crucial areas like collateral free loans, timely bank sanctions, release of margin money subsidy and loan instalment, coverage of credit guarantee scheme, achievement of social category targets of SC, ST, minority, women etc.

The meeting will encourage all the stakeholders and will leads to better implementation of PMEGP Scheme in Jammu and Kashmir Region, thereby achieving the set targets in time and providing better employment opportunities to the youths.

The position was reviewed in the meeting and also the bottlenecks were examined.

In the meantime, State Director, KVIC J&K emphasised upon the banks to look into the cases which been rejected by various banks and expedite process of claiming of Margin Money (Subsidy) as there is exemption of EDP upto30 September 2020. Dy. CEO (NZ) advised State Director KVIC J&K to hold the meetings with Director Industries and Commerce of Jammu and Kashmir Regions, and Secretary KVIB, J&K for expedition of PMEGP cases so that the target set by the Government of India is achieved within the time. Further, Lead District Managers, Director RSETI's and Sponsoring Agencies also raised points for the betterment of PMEGP.

KVIC Organises Bankers Meeting on PMEGP

PMTC KVIC Pampore Started Different ki[nds of] training programs in Central Kashm[ir]

Budgam; : Production Cum Marketing Cum Training Center/Khadi and Village Industries Commission Pampore Today started four training programmes at far flung villages of central Kashmir District Budgam. First training program on shawl embroidery course was started at check shera Khansahib Budgam, second training on kani shawl weaving was started at checkshera Budgam. The third training course on willow works and fourth training on carpet weaving was started at checkshera Khansahib Budgam.The training programmes were inaugurated by Shri Anil Kumar Sharma Principal PMTC Pampore. Besides, staff of PMTC were also present on the occasions.

प्रेस कवरेज

बैंकों के पास लंबित आवेदनों का शीघ्र से शीघ्र करें निस्तारण : शुक्ला

- वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैंक प्रतिनिधियों से किया आग्रह
- पीएमईजीपी योजना देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगी

शिमला, 11 सितंबर (सवेरा) : खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की बैंकों के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सत्य नारायण शुक्ला, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली ने की। बैठक में राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, राज्य के सहकारी बैंकों के अधिकारियों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं उद्योग निदेशालय के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में पीएमईजीपी योजना की बैंकवार, जिलेवार व अभिकरणवार समीक्षा की गई और आंकलन किया गया कि वर्तमान में देश में व्याप्त वैश्विक समस्या कोविड-19 के कारण योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, स्वरोजगार व आत्म निर्भर भारत के लिए भारत सरकार की एक मुख्य योजना है। वर्तमान में व्याप्त वैश्विक समस्या के दौरान भी यह योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में छोटे व मझोले उद्योग स्थापित कर रोजगार सृजन कर सकती है। जोकि देश के आर्थिक विकास में महत्व पूर्ण भूमिका प्रदान करेगी। शुक्ला ने बताया कि राज्य के सभी बैंकों के पास पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर शुक्रवार को योजना के अंतर्गत 570 आवेदन 19.50 करोड़ के निस्तारण के लिए लंबित है। उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि बैंकों के पास लंबित आवेदनों का निस्तारण शीघ्र से शीघ्र करें।

हर हाथ को काम देने को उठाया जा रहा कदम

पहल
- सामान्य सुविधा केंद्र व खादी भंडार का उद्घाटन
- सेवाश्रम पर काम कर प्रतिदिन कमा सकते हैं एक हजार रुपये

जागरण संवाददाता, कासिमाबाद (गाजीपुर) : क्षेत्र की ग्राम पंचायत कटयालहंग व कादीपुर में सामान्य सुविधा केंद्र, रेडीमेड गारमेंट्स यूनिट व खादी भंडार का उद्घाटन शनिवार को हुआ। इस दौरान खादी ग्रामोद्योग विभाग वाराणसी के डायरेक्टर डीएस भाटी ने क्षेत्रीय ग्रामीणों और कामगारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका विभाग भारत सरकार की योजना के तहत हर हाथ को काम देने के तहत कदम उठा रहा है, और खादी को जन-जन तक पहुंचाने की मुहिम चलाई जा रही है।

रविवार को खादी भंडार के उद्घाटन मौके पर मौजूद खादी ग्रामोद्योग वाराणसी के डायरेक्टर डीएस भाटी • जागरण

खादी ग्राम उद्योग भारत सरकार के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से कटयालहंग व कादीपुर में शुरू किए गए सेवाश्रम पर लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं जानी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से यह भी कहा कि भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत हर हाथ को काम देने के क्रम में हमारा विभाग भी ग्रामीण अंचल में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ-साथ सिलाई कढ़ाई बुनाई में कुशल महिलाओं को भी रोजगार देने का काम कर रहा है। संस्था के महामंत्री राजेश कुमार यादव ने कहा कि सेवाश्रम पर काम करने वाले कामगार प्रतिदिन एक हजार रुपये से ऊपर भी की भी कमाई आराम से कर सकेंगे, इससे उनके घर को एक अतिरिक्त आय भी मिलेगी और सरकार की योजनाओं के तहत उनका जीवन स्तर भी सुधर सकेगा। वाराणसी के सह निदेशक दिनेश कुमार सिंह, केपी मिश्रा, अनूप सिंह, प्रशांत कुमार, जेपी श्रीवास्तव, बब्लू सिंह, गुड्डू सिंह, सत्येंद्र तिवारी, पवन यादव, सुनील आदि थे।

किसी के बहकावे में न आएं
बोरिंग में ड्यूरो पाइप ही लगाएं

ऋण आवेदनों का जल्द निपटारा करें बैंक

जागरण संवाददाता, शिमला : खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें बैंक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि लंबित आवेदनों का निस्तारण शीघ्र करें। बैठक की अध्यक्षता सत्य नारायण शुक्ला उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय ने की। बैठक में बैंकों के अधिकारियों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं उद्योग निदेशालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में पीएमईजीपी योजना की बैंकवार, जिलेवार व अभिकरणवार समीक्षा और आकलन किया गया। शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, स्वरोजगार व आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत सरकार की एक मुख्य योजना है। वर्तमान में व्याप्त वैश्विक समस्या के दौरान भी यह योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में छोटे व मझोले उद्योग स्थापित कर रोजगार सृजन कर सकती है। समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी बैंकों के पास पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर योजना के अंतर्गत 570 आवेदन 19.50 करोड़ रुपये के निस्तारण हेतु लंबित हैं। उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (हिमाचल प्रदेश) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निदेशक, उद्योग निदेशालय को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त करें और आवेदनों का आकलन कर उन्हें संबंधित बैंकों को अग्रेषित करें।

बैठक में एसएलबीसी प्रतिनिधि, यूको बैंक आरएस डढवाल ने आश्वासन दिया गया कि योजना के अंतर्गत राज्य में शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की जाएगी। बैठक में मांगी राम, राज्य निदेशक खादी और ग्रामोद्योग द्वारा राज्य में योजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

Bankers Review-cum-Monitoring Committee meeting under PMEGP held

Commissioner/ Secretary I&C Department, MK Dwivedi chairing a meeting.

STATE TIMES NEWS

JAMMU: Bankers Review-cum Monitoring Committee meeting under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) was held under the chairmanship of Commissioner/ Secretary Industries & Commerce Department.

The meeting was attended by Director Industries & Commerce, Jammu, Director Industries & Commerce, Kashmir, Director Planning Industries & Commerce Department, Secretary/ CEO J&K KVIB, Director Khadi & Village Industries Commission and Officers / Bankers from various Banks.

The meeting was focused at reviewing the agency wise and bank-wise performance under PMEGP for the year 2019-20 and 2020-21.

During the meeting, it was informed that against the targets for establishment of 1,920 units involving margin money of Rs. 5758.60 lakh, margin money to the tune of Rs. 9908.12 lakh was released by Government of India for establishment of 4,992 units thereby creating employment opportunities for 39,936 persons, during the previous year FY, 2019-20.

Additionally, for the current FY, a target for establishment of 2,600 units involving margin money of Rs. 7804.21 lakh has been fixed for UT of J&K.

Against the said targets, an amount of Rs. 3280.14 lakh has been disbursed for establishment of 1,668 units.

Commissioner/ Secretary I&C Department impressed upon officers to ensure that the scheme benefits reach to people living in all districts especially in remote areas of the UT.

He enjoined officers to organize awareness programmes so that the people residing in far flung areas are sensitized about the scheme.

He also noted with satisfaction that 35.5 per cent units under PMEGP have been set up by women entrepreneurs.

22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

बैंकों के पास लंबित आवेदनों का जल्द करें निस्तारण

शिमला। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य की बैंकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी खादी और ग्रामोद्योग आयोग सत्य नारायण शुक्ला ने की। बैठक में पीएमईजीपी योजना की बैंकवार, जिलेवार और अभिकरणवार समीक्षा की गई। इसमें आकलन किया गया कि वर्तमान में देश में व्याप्त वैश्विक समस्या कोविड-19 के कारण योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई है, यह खेद का विषय है। वर्तमान में व्याप्त वैश्विक समस्या के दौरान भी यह योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में छोटे व मझोले उद्योग स्थापित कर रोजगार सृजन कर सकती है, जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगी। सभी बैंकों के पास पीएमईजीपीऑन लाइन पोर्टल पर योजना के तहत 570 आवेदन लंबित हैं। उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि बैंकों के पास लंबित आवेदनों का निस्तारण शीघ्र करें।

मेडिकल इमरजेंसी रिक्रूटमेंट

केवीआईसी सोशल मीडिया पर

फेसबुक पर

केवीआईसी सोशल मीडिया पर

इंस्टाग्राम पर

• Special Day posts •

Khadi India

To revolve around
Paradigm of ancient & traditional is our diorism

Village industries products are nature's gift to mankind and offer a variety of article for every memorable occasion. Exquisite palmyrah articles, artistically designed pottery presentations, favourite fibre fantasies and carved stoneware are all having utility value of their own.
Whether it is buying of producing those artefacts, it is an experience by itself.
How it is so you can know when you contact.

Visit your nearest khadi Bhavan / Bhandar

KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, (Govt. of India)
Gramodaya, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai-400 056.
Phone: 022- 26714320, 26716323
Website: www.kvic.org.in